Implementation of P.M.'s Rozgar Yojana

2640. SHRI RAHASBIHARI BAR IK : Will the PRIME MINISTER be pleased lo state :

(a) the year of the inception of the Prime Minister's Ro.zgar Yojana;

(b) the details of the employment generated under the Prime Minister's Rozgur Yojana so for; and.

(c) the details of steps taken by different State Governments to implement the Yojana7

THE MINISTER OF STATr: IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) The Prime Minister's Rozgar Yojana came in operation on 2nd October, 1993 in all urban areas oi the country- Since 1-4-94 the Yojana is under implementation in rural as well as urban areas.

(b) As per reports received from States UTs, under Prime Minister's Rozgar Yojanas loans were sanctioned to 63,737 beneficiaries till end of October, 1994. Each of these enterprises is expected to provide employinen[1] to two persons on an average.

(c) The main steps taken by the State Governments are as follows :

(i) State Governments have allocated districtwise targets.

(ii) State Governments/UTs have constituted district task forces at district level to receive and screen the applications for recom. mending to the banks for sanctioning of loans

(iii) District PMRY Committee under the chairmanship of Collector and State PMRY Committee at the State/UT level have been constituted to monitor the progress and ensure effective implementation of che scheme.

(iv) Beneficiaries .anctioned loan undi> PMRY are provided training. Arrangement of training is the responsibility of the States; UTs.

Medical Allowance to Spouse

2641. SHRI DIGVIJAY SINGH : Will the 1 RIME MINISTER be pleased to state :

(.a) whether Government are considering to extend/enhance the medical allowance to t.iose where wife ant! husband are working in tae same PSIj to make them at par with those working in different PSUs where both arc iig medical allowance separately;

(b) if so, whether they will be given arrears of the same f inee the" stoppage of the :.arpe; and

(c) if not, the reasons thereto!

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI) : (a) Where husband and wife iire PSt employees either of thtm will have to make a declaration that he or she is dependent on the other for the putposc of medical reimbursement to regulate the dependents' claims like that of the spouse. There is no proposal under consideration i of the Govt, to change the existing arrangement.

(b) and (c) Do not arise in view of the (a) above.

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत लाभ

2642. **श्रीमती सुष्मा स्वराज :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में शिक्षित नवयुवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने प्रधान मंत्री रोजगार योजना शुरु की है ,

(ख) यदि हां, तो इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 1993-94 के दौरान और सितम्बर, 1994 तक कितने शिक्षित नवयुवकों को ऋण दिये गये हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त अवधि में अनेक शिक्षित बेरोजगारों ने स्वरोजगार हेतु इस योजना के तहत आवेदन किये थे ;

(घ) यदि हां, तो 1993-94 के दौरान और अप्रैल 1994 से सितम्बर, 1994 तक उनकी संख्या कितनी-कितनी है ; और

(ङ) नवयुवकों को ऋण देने के मामले में प्राथमिकता देने के क्या मानदंड थे और किस-किस राज्य में कितने-कितने नवयुवकों को ऋण दिया गया ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) (क) जी हां ।

(ख) प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत 1993-94 और 1994-95 (1-4-94 से 30-9-94 तक) के दौरान शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

क्र०सं०	वर्ष	प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत उन शिक्षित बेरोजगार युवाओं की संख्या, जिनको बैंकों द्वारा ऋण मंजूर किया गया है (संख्या)
1	1993-94	31,797
2	1994-95 (1-4-94-30-9-94)	18,525

(ग) जी, हां ।

(घ) 1993-94 और 1994-95 (1 अप्रैल 94 से 30 सितम्बर 94 तक) के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए उन शिक्षित बेरोजगार युवाओं के ब्यौरे इस प्रकार हैं, जिन्होंने सहायता के लिए आवेदन दिये थे :

क्र०सं०	वर्ष	प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत उन शिक्षित बेरोजगार युवाओं की संख्या जिन्होंने सहायता के लिए आवेदन किए थे (संख्या)
1	1993-94	2,29,418
2	1994-95 (1-4-94—30-9-94)	5,31,734

(ङ) जिला उद्योग केन्द्रों में बेरोजगार शिक्षित युवाओं से प्राप्त आवेदनों की जांच निम्नलिखित आधार पर की जाती है :—

(1) उम्र :—18 से 35 वर्ष के बीच ।

(2) **योग्यता** :—मैट्रीक (उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण) अथवा आई. टी. आई. उत्तीर्ण अथवा कम से कम 6 महीने की अवधि तक सरकारी प्रायोजित तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त ।

(3) **निवास** :—कम से कम तीन वर्ष तक उस क्षेत्र का स्थायी निवासी हो ।

(4) **पारिवारिक आय** :—माता-पिता की वार्षिक आय 24,000 रुपये तक तथा लाभभोगी के परिवार की वार्षिक आय 24,000 रु. तक ।

(5) **व्यतिक्रम** :—किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्थान/सहकारी बैंक में उसे चूककर्ता नहीं होना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त, जिला उद्योग, केन्द्रों में प्राप्त सभी आवेदनों की जांच वित्तीय जीव्यता, तकनीकी जीव्यता और अन्य यथा आवश्यक मानदण्डों के आधार पर की जाती हैं। इन मानदण्डों को पूरा करने वाले आवेदन बैंकों को आगे विचार करने हेतु भेजे जाते हैं।

1993-94 के दौरान ऐसे शिक्षित बेरोजगार युवाओं को जिन्हें प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत ऋण मंजूर किया गया है, के राज्यवार आंकड़े और वर्ष 1994-95 में 1-4-94 से 30-9-94 तक की अवधि में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत ऋण स्वीकृत किये गये शिक्षित बेरोजगार युवाओं के राज्यवार आंकड़े संलग्न अनुपत्र में दिये गये हैं। [देखिए परिशिष्ट 172 (अनुपत्र 64)]।

विदेशी निवेश को प्रोत्साहन

2643 **श्रीमति सुष्मा स्वराज :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1991 से विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक सुविधाओं की घोषणा की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उन घोषणाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि जून, 1991 से सितम्बर, 1994 तक अनेक विदेशी संस्थानों ने भारत में निवेश करने की पेशकश की है,

(घ) यदि हां, तो अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, कनाडा, चीन, जापान और जर्मनी ने प्रत्येक अवधि में निवेश हेतु कितने-कितने प्रस्ताव किये और सरकार ने उनमें से कितने-कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी है, और

(ङ) सितम्बर, 1994 तक किस-किस देश के कुल कितने-कितने प्रस्तावों का निष्पादन हुआ है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) जी हां। 24 जुलाई, 1991 को संसद के दोनों सदनों को संभाषणत्व पर रखे गए औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित मानदंडों के अधीन उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों (अर्थात औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य के अनुबंध-3 में सूचीबद्ध उद्योग) में 51% तक इक्विटी पूंजी वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्तावों को स्वतः मंजूरी देता है। स्वतः अनुमोदन के लिए उपर्युक्त मानदंडों में न आने वाले विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अन्य प्रस्तावों पर सरकार द्वारा सामान्य प्रक्रिया के अधीन विचार किया जाता है।

(ग) और (घ) 1991 की नई औद्योगिक नीति ने विदेशी संस्थाओं सहित निवेशकों में पर्याप्त रूची पैदा की है। 1991 से अक्तूबर, 1994 के दौरान अमेरिका, फ्रांस, इंगलैंड रूस कनाडा, चीन, जापान और जर्मनी की कंपनियों/संस्थाओं से निवेश के लिए प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों की देशवार संख्या विवरण I में दिए गए हैं (नीचे देखिए)।

(ङ) 1991 से अक्तूबर, 1994 की अवधि के दौरान इन देशों की कंपनियों/संस्थाओं से प्राप्त वास्तविक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश विवरण II में दिए गए हैं (नीचे देखिए)। तथापि, कार्यान्वित किए गए प्रस्तावों की संख्या से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

विवरण-I

	1991 से 1994 (अक्तूबर तक) के दौरान अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों की कुल संख्या
संयुक्त राज्य अमेरिका	507
फ्रांस	77
इंगलैंड	275
रूस	47
कनाडा	29
चीन	14
जापान	59
जर्मनी	267